भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2457

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

स्कूलों और कॉलेजों में मूलभूत वित्तीय शिक्षा

†2457. **श्री पी. सी. मोहन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में बैंकिंग, बचत, बजट और कराधान जैसे विषयों सहित मूलभूत वित्तीय शिक्षा शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो एनईपी 2020 के अंतर्गत या एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूजीसी या वित्तीय नियामक निकायों जैसे संस्थानों के सहयोग से की गई ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर बेंगलुरु जैसे शहरी केंद्रों में व्यक्तिगत वित्त और कर संबंधी मूलभूत बातों पर कोई पायलट मॉड्यूल या जागरूकता कार्यक्रम लागू किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि वित्तीय साक्षरता को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और शिक्षा बोर्डों के छात्रों के लिए व्यावहारिक और सुलभ रूप से एकीकृत किया जाए; और

(ङ.) इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने और दीर्घकालिक रूप से युवाओं की वित्तीय जागरूकता, डिजिटल वित्तीय समावेशन और कर अनुपालन पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, यदि कोई हो, रोडमैप और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और उसके बाद स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 के अनुवर्ती के रूप में, स्कूल शिक्षा के सभी चरणों के

लिए विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) में पाठ्यपुस्तक विकास समितियों का गठन किया गया है। वाणिज्य में पाठ्यपुस्तक विकास दल (टीडीटी-वाणिज्य) का भी गठन किया गया है। टीडीटी-कॉमर्स द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्या में माध्यमिक स्तर पर वित्तीय साक्षरता और कराधान के विभिन्न घटकों पर सामग्री शामिल है। मध्य चरण (कक्षा VI-VIII) के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें *"एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड"* शिक्षार्थियों के बीच वित्तीय साक्षरता विकसित करने के लिए काफी गुंजाइश प्रदान करती हैं। इस पाठ्यक्रम में मुद्रा के विकास, बैंकिंग प्रणाली, ऋण के रूप, मुद्रा और अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे स्टॉक एक्सचेंज आदि जैसे विषय शामिल हैं।

माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 और 12) पर अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में बजटीय प्रक्रिया से संबंधित सामग्री और बजट को समझने के लिए विभिन्न अवधारणाएं शामिल हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों को निर्धारित करता है।

समग्र शिक्षा के व्यावसायिक शिक्षा घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत शामिल स्कूलों में कक्षा IX से XII तक के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। वित्तीय साक्षरता व्यावसायिक शिक्षा द्वारा कवर किया गया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र के तहत, इस विभाग द्वारा इस घटक के तहत 4 नौकरी भूमिकाओं को मंजूरी दी जाती है जो इस प्रकार हैं:

i. माइक्रोफाइनेंस कार्यकारी,
ii. व्यवसाय संवाददाता/सूत्रधार,
iii. एमआईएस डेटा विश्लेषक - वित्तीय सेवाएं,
iv. ग्राहक सेवा सहयोगी - वित्तीय सेवाएँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 37 क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) सहित बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) के साथ एक बैठक आयोजित की, जहां उन्हें शिक्षा जगत में कौशल को शामिल करने के बारे में सूचित किया गया, जिसमें स्टडी वेब ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडस (स्वयम) प्लस प्लेटफॉर्म के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुपालन में अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रावधान शामिल है, जिसे विशेष रूप से कौशल और रोजगार के उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र-शैक्षिक संचार संघ (सीईसी) ने स्वयम के लिए राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर के रूप में, स्वयम प्लेटफॉर्म (www.swayam.gov.in) के माध्यम से उच्च

शिक्षा के लिए वित्तीय शिक्षा पर नौ पाठ्यक्रम विकसित और पेश किए हैं। पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है: -

i. मुद्रा और वित्तीय बाजार (5 क्रेडिट)
ii. वित्तीय लेखांकन (5 क्रेडिट)
iii. बैंकिंग और बीमा के मूल सिद्धांत (2 क्रेडिट)
iv. भारत में बैंकिंग, बीमा और उपभोक्ता संरक्षण कानून (4 क्रेडिट)
v. बैंकिंग और बीमा (4 क्रेडिट)
vi. वित्तीय बाजार, संस्थान और वित्तीय सेवाएं (5 क्रेडिट)
vii. आयकर कानून और प्रैक्टिस (5 क्रेडिट)
viii. आयकर (5 क्रेडिट)
ix. अप्रत्यक्ष कर कानून (5 क्रेडिट)

कर्नाटक सरकार के अनुसार, कक्षा 6 के बाद से विभिन्न विषयों के अनुशासनात्मक ज्ञान का अभ्यास किया जाता है। राज्य के पाठ्यक्रम में सरकार की वित्तीय शिक्षा, बैंकिंग, बजट, कराधान, योजना और वित्तीय नीतियां शामिल हैं, जिन्हें कक्षा 6 से 12 तक क्रमिक रूप से शुरू किया जाता है, जिसमें सामाजिक विज्ञान और गणित में अलग-अलग अध्याय प्रदान किए जाते हैं। राज्य ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सहयोग से इस संबंध में पहल भी की है। वर्ष 2023-24 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग (डीएसईआरटी), कर्नाटक द्वारा विकसित जीवन कौशल पर मॉड्यूल में वित्तीय साक्षरता भी शामिल थी, और सभी शिक्षकों को कैस्केड मोड के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। राज्य ने छात्रों के बीच मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी, संवैधानिक जागरूकता, वित्तीय-डिजिटल मूल्यों और जीवन कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 12 के लिए मूल्य शिक्षा पाठ्यपुस्तकें भी विकसित की हैं।

****